Date - 21 April 2022

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन

- हाल ही में, भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) का वर्चुअल आयोजन किया गया था।
- प्रतिभागियों ने अपने-अपने देशों में आतंकवाद से संबंधित विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की और आतंकवाद के मामलों पर मुकदमा चलाने, विदेशी लड़ाकों से निपटने की रणनीति और इंटरनेट और सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुकाबला करने में अपने अनुभव साझा किए।

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी):

- सीएससी का गठन वर्ष 2011 में एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था जिसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल थे।
- इसमें मॉरीशस को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पांचवीं बैठक में चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।
- बांग्लादेश और सेशेल्स ने पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लिया और उन्हें समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया।
- परिकल्पित लक्ष्य: सीएससी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पांचवीं बैठक ने निम्नलिखित पांच स्तंभों में क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की:
    - सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा
    - आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला
    - अवैध व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करना
    - साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी की सुरक्षा
    - मानवीय सहायता और आपदा राहत

Yojna IAS

महत्त्व:

- सीएससी को क्षेत्रीय सहयोग और साझा सुरक्षा उद्देश्यों को रेखांकित करने के लिए हिंद महासागर तक भारत की पहुंच के रूप में देखा जाता है।
- चीन का मुकाबला: सीएससी रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में चीन के प्रभाव को सीमित करने और सदस्य देशों में चीन की उपस्थिति को कम करने की उम्मीद करता है।
- समुद्री सुरक्षा: रणनीतिक चोकपॉइंट द्वीपों के साथ-साथ भारत के पास लगभग 7500 किमी की एक बड़ी तटरेखा है। समुद्री सुरक्षा देश की प्राथमिकता है, जिसमें सीएससी अहम भूमिका निभाता है।
- सागर विजन के साथ तालमेल: यह समूह भारत के "सागर: सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास" के भारत के दृष्टिकोण और इंडिया क्वाड ग्रुपिंग का सदस्य होने के अनुरूप है।
- उदीयमान उप-क्षेत्रवाद: हिंद महासागर क्षेत्र के 6 देशों का एक साझा समुद्री और सुरक्षा मंच पर एक साथ आना उप-क्षेत्रवाद के विकास को इंगित करता है और व्यापक वैश्विक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- संबद्ध चुनौती: भले ही छह देशों के रणनीतिक हित हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में संरेखित हों, लेकिन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) को चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए CSC को एक संस्था के रूप में ढालने के प्रयास को पूरा करना चाहिए।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक, 2008, 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के अधिनियमन के साथ अस्तित्व में आई।
- 2008 के मुंबई हमलों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई थी, क्योंकि इस घटना के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई थी।

Yojna IAS

तिमोर लेस्ते

- हाल ही में, पूर्वी तिमोर (तिमोर लेस्ते), जिसे एशिया के नवीनतम लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, ने राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे और अंतिम दौर का समापन किया।

पूर्वी तिमोर के बारे में मुख्य बातें:

इतिहास:

- इस क्षेत्र पर 18वीं शताब्दी में पुर्तगाल का उपनिवेश था और 1975 तक पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहा।
- जब पुर्तगाली इस क्षेत्र से हट गए, तो इंडोनेशिया ने उस पर आक्रमण किया और पूर्वी तिमोर को अपने 27वें प्रांत के रूप में स्थापित किया।
- पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता के लिए एक लंबा और खूनी संघर्ष चला, जिसमें कम से कम 100,000 लोग मारे गए।
- 1999 में, पूर्वी तिमोरीस ने संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण वाले जनमत संग्रह में स्वतंत्रता के लिए मतदान किया, लेकिन इसने हिंसक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जब तक कि शांति सेना को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई।
- देश को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई थी।
- पूर्वी तिमोर ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) का सदस्य बनने के लिए भी आवेदन किया है।
- वर्तमान में इसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

भौगोलिक स्थिति:

- पूर्वी तिमोर दक्षिण-पूर्व में तिमोर सागर, उत्तर में वेटार जलडमरूमध्य, उत्तर-पश्चिम में ओमबाई जलडमरूमध्य और दक्षिण-पश्चिम में पश्चिम तिमोर (पूर्वी नुसा तेंगारा के इंडोनेशियाई प्रांत का हिस्सा) से घिरा है।
- पूर्वी तिमोर में तिमोर द्वीप का पूर्वी भाग शामिल है, जिसका पश्चिमी आधा भाग इंडोनेशिया का हिस्सा है।
- यह 15,000 वर्ग किमी के भूमि क्षेत्र को कवर करता है, जो इज़राइल से थोड़ा छोटा है और इसके 3 मिलियन लोग मुख्य रूप से रोमन कैथोलिक हैं।

अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में:

राजनीति:

- आजादी के बाद से लगभग 20 वर्षों में, पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों में कई लोगों का समान रूप से वर्चस्व रहा है।

Yojna IAS

- अपनी राजनीतिक व्यवस्था में, राष्ट्रपति कुछ कार्यकारी शक्तियों को भी साझा करता है और सरकार की नियुक्ति करता है और मंत्रियों को वीटो करने या संसद को भंग करने की शक्ति रखता है।

अर्थव्यवस्था:

- देश अपने अपतटीय तेल और गैस भंडार से राजस्व पर निर्भर करता है जो कि इसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 90% हिस्सा है।
- ग्रेटर सनराइज गैस फील्ड के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका एक समझौता है, जिसका अनुमानित मूल्य 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- इसका मुख्य राजस्व क्षेत्र, बायू अंडरन गैस क्षेत्र, वर्ष 2023 तक सूखने के कगार पर है और देश अब ऑस्ट्रेलिया में कंपनियों के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है ताकि इसे कार्बन कैप्चर सुविधाओं में परिवर्तित किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले

Yojna IAS

- सर्वोच्च न्यायालय के कई वर्तमान न्यायाधीश वर्ष 2022 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष शीर्ष न्यायालय में कई पद रिक्त हो जाएंगे।

संबंधित चिंताएं:

- सुप्रीम कोर्ट में ये सेवानिवृत्ति ऐसे समय में हो रही है जब अदालत में बड़ी संख्या में मामले लंबित होने के कारण, विशेष रूप से महामारी की क्रूर लहरों के बाद, अदालत खुद को स्थिर करने की प्रक्रिया में है।
- भारत की कानूनी प्रणाली में दुनिया में 'सबसे बड़ा लंबित केस बैकलॉग' है – लगभग 30 मिलियन मामले लंबित हैं।
- यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो इसकी अपनी कानूनी प्रणाली की खामियों को दर्शाती है।
- और इस बैकलॉग के कारण, भारत की जेलों में अधिकांश कैदी विचाराधीन विचाराधीन हैं जो मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले:

- सर्वोच्च न्यायालय के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2022 तक शीर्ष अदालत में 70,362 मामले लंबित हैं।
- इनमें से 19% से अधिक मामले 'न्यायिक सुनवाई' के लिए अदालत की पीठ के समक्ष पेश होने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि आवश्यक प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।
- 52,110 मामले अभी भी शुरुआती चरण में हैं, जबकि 18,522 मामले नियमित सुनवाई से जुड़े हैं।

- संविधान पीठ के समक्ष कुल मामलों (मुख्य और संबद्ध मामले) की संख्या 422 है।
- 'वर्चुअल सिस्टम' के दो साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 'पूर्ण शारीरिक सुनवाई' फिर से शुरू की है।

लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम:

- सरकार को एक कुशल और जिम्मेदार 'वादी' बनाने के लिए "राष्ट्रीय मुकदमा नीति 2010" लागू की गई है।
- 'राष्ट्रीय मुकदमा नीति' 2010 के अनुसार सभी राज्यों द्वारा 'राज्य मुकदमा नीतियां' तैयार की गई हैं।
- 'कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस)' 2015 में तैयार की गई थी जिसका उद्देश्य उन मामलों पर नज़र रखना था जिनमें सरकार एक पक्ष है।
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि पहले से ही भीड़भाड़ वाली जेलों पर बोझ डालने के बजाय 6 महीने या एक साल के कारावास की सजा पाने वाले अपराधियों को समाज सेवा कर्तव्यों का आवंटन किया जाना चाहिए।

समय पर मांग:

- राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति में संशोधन करें।
- मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने के लिए 'वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र' को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- सरकार और न्यायपालिका के बीच समन्वित कार्रवाई की जानी चाहिए।
- उच्च न्यायालयों पर बोझ कम करने के लिए निचली अदालतों में न्यायिक क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए।
- न्यायपालिका पर खर्च बढ़ाया जाना चाहिए।
- कोर्ट केस मैनेजमेंट और कोर्ट ऑटोमेशन सिस्टम में सुधार किया जाना चाहिए।
- विषय-विशिष्ट 'पेठों' का गठन।
- मजबूत आंतरिक विवाद समाधान तंत्र।
- न्यायाधीशों को छोटे और अधिक सटीक निर्णय लिखने चाहिए।

Swadeep Kumar

Yojna IAS